

# Principle of Maximum Social advantage

## अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त

राज्य के विधीय नीति विधायक के अन्तर्गत सरकार आज व लाभ सम्पन्नी या गुरुत्व कार्य को करती है। लेकिन लाभ और लाभ का सांजस्य कैसे है इसपर विभिन्न आर्थशास्त्रियों के अलग अलग विचारधारा है। प्राचीन विचारधारा के अनुसार सरकार वही कार्य करनी जाती थी जो कि कर्म से कर्म कर लगानी थी और कर्म से कर्म रकम करती है। इसलिए J. B. Say ने कहा कि "सार्वजनिक विन की वही योजना सबसे उपयुक्त होती है जिसमें न्यूनतम लाभ किया जाता है और सब करों में वही सबसे अच्छा होता है जिसकी मात्रा सबसे कम होती है।"

आधुनिक आर्थशास्त्रियों के अनुसार सरकार के न सभी कर अभिशाप है और न सभी लाभ अनुत्पादक होते हैं। वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही मुख्य उद्देश्य है। जिसमें सरकार का आज और भव्य शक्ति में स्वरूप का सांजस्य है कि समाज को अधिकतम लाभ की प्राप्ति है।

अधिकतम सामाजिक लाभ का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। डाल्टन के अनुसार "राजस्व की सर्वोत्तम व्यवस्था वही कहलायगी जिसकी क्रियाओं में अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति होती है।" यदि सरकार के किसी कार्य से या कर लेने से कुछ व्यक्ति व्यक्तियों को नुकसान है पर सम्पूर्ण समाज का कल्याण है तो वह राजस्व के सिद्धान्त के अनुसार न्यायोचित माना जाता है।

राजस्व के सिद्धान्त के अनुसार सरकार इस प्रकार कर ले तथा उसे व्यय करे कि अनुपयोगिताओं से ऊपर उपयोगिताओं की मात्रा अधिकतम हो। अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए सरकार की निम्न क्रियाएँ अभिप्राय हैं। -

1. आय के वितरण में परिवर्तन -

सरकार कर के रूप में धनी वर्ग के लोगों से आय प्राप्त करती है और उसे मध्यम वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय करती है। इससे व्यय की असमानता कम होती है जो अधिकतम कल्याण का बहाल है।

2. उत्पादन में परिवर्तन -

कर चुकाने के लिए या तो लोग उपयोग कम करते हैं या बचत कम करते हैं जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए प्रजातिशैल कर का लगाना आवश्यक है।

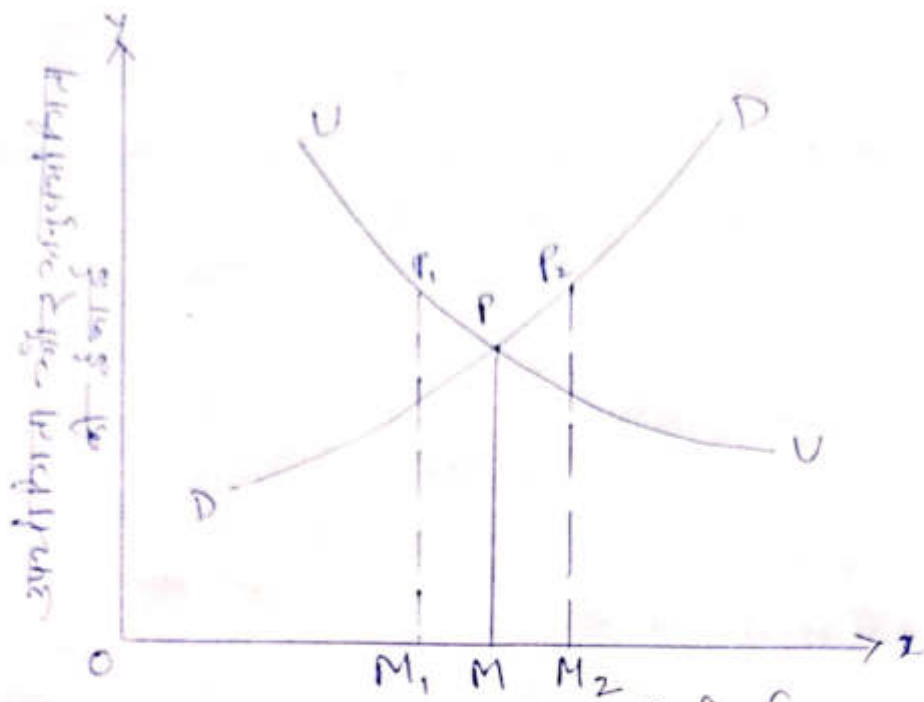
3. बचत पर प्रभाव -

अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए यह आवश्यक है कि कर इस प्रकार लगाया जाय जिससे कि समाज में बचत का प्रोत्साहन मिले। अतएव अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए उक्त खारी बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। अधिकतम सामाजिक लाभ को सिद्धान्त उपयोगिता धारा सिद्धान्त पर आधारित है। सरकारें प्रायः धनी वर्गों पर ऊँचे कर लगाती हैं और इनसे प्राप्त होने वाली आय मध्यम वर्गों पर व्यय की जाती है। धनी वर्गों पर करारोपण से उनकी सीमान्त उपयोगिता

घटती है इसी ओर जब इन करो से प्राप्त लाभ गरीबों की सुविधाओं पर खर्च किया जाता है तो इससे उनकी सीमान्त उपभोगिता शुरू में बढ़ती है लेकिन अधिकधिक खर्च होने पर उनकी सीमान्त उपभोगिता घटनी शुरू हो जाती है। डाल्टन के अनुसार "यह प्रक्रिया सरकार द्वारा उस सीमा तक प्रचलित रखी जानी चाहिए जब तक बढ़ती हुई सीमान्त उपभोगिता गरीबों की बढ़ती हुई सीमान्त उपभोगिता के बराबर नहीं हो जाती। अधिक-कर की मात्रा में वृद्धि से प्राप्त होने वाली अनुपभोगिता कर से प्राप्त रकम की व्यय करने से समाज को प्राप्त होने वाली उपभोगिता के बराबर होना चाहिए। उपयुक्त सिद्धान्त को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है -

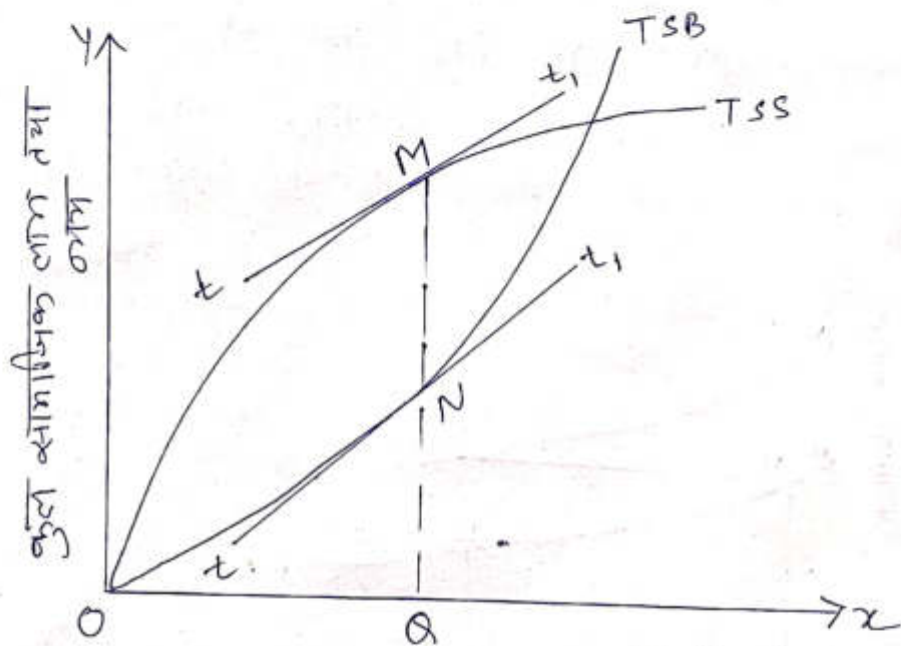
इकाई	करारोपण से होने वाली अनुपभोगिता	कर से प्राप्त रकम की व्यय करने से प्राप्त उपभोगिता
1	1	36
2	4	28
3	8	24
4	12	22
<u>5</u>	<u>19</u>	<u>19</u>
6	26	7
7	34	2

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि पाँचवे इकाई से अधिक कुल करारोपण नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि यह अधिक होता है तो सामाजिक लाभ अधिकतम नहीं हो सकता। इसे ~~कर~~ रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है -



कर एवं लाभ की ईकाई  
 उपयुक्त चित्र में  $Ox$  रेखा पर कर और लाभ की  
 ईकाई तथा  $Oy$  रेखा पर उपभोगिता और अनुपभोगिता  
 का दिखाया गया है।  $UU$  वक्र सरकारी लाभ की  
 प्रत्येक ईकाई से क्रमशः घटती हुई उपभोगिता को  
 व्यक्त करता है तथा  $DD$  वक्र कर की प्रत्येक ईकाई  
 से क्रमशः बढ़ती हुई अनुपभोगिता को व्यक्त करता है।  
 दोनों वक्र एक दूसरे को  $P$  बिन्दु पर काटते हैं।  
 यह Equilibrium point साम्य बिन्दु होता है।  
 बिन्दु पर सामाजिक लाभ अर्थात् अनुपभोगिता से  
 सामाजिक लाभ अर्थात् उपभोगिता एक दूसरे के  
 बराबर होते हैं।  $OM$  मात्रा से अधिक कर लेने  
 तथा लाभ करने से अनुपभोगिता अधिक और  
 उपभोगिता कम हो जाता है। जो  $P_2 M_2$  रेखा से  
 स्पष्ट है और  $OM$  से कम कर लेने तथा लाभ  
 करने से उपभोगिता अधिक और अनुपभोगिता कम  
 हो जाती है। जैसा कि  $P_1 M_1$  रेखा से स्पष्ट है।  
 अतः  $OM$  कर और लाभ की आदर्श मात्रा से

ही सामाजिक लाभ अधिकतम हो सकता है।  
 अधिकतम सामाजिक लाभ की व्याख्या कुल सामाजिक  
 लाभ तथा कुल सामाजिक लाभ वक्र अंतरा की स्पष्ट  
 किया जा सकता है। अधिकतम सामाजिक लाभ उस  
 बिन्दु पर प्राप्त होगा जहाँ कुल सामाजिक लाभ तथा कुल  
 सामाजिक लाभ का अंतर सबसे अधिक है। इस  
 चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है -



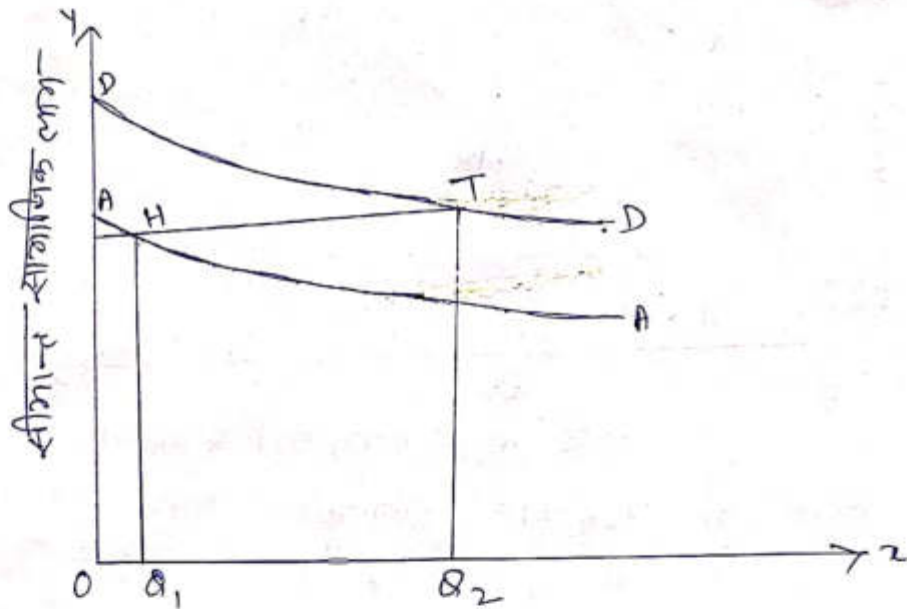
कर तथा व्यय की ईकाईयों

उपरोक्त चित्र में TSB वक्र सार्वजनिक व्यय से प्राप्त कुल सामाजिक लाभ को दर्शाता है जिसका ढाल ऊपर की ओर उठता हुआ प्राप्त होता है जो दर्शाता है कि जैसे जैसे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती जाती है कुल सामाजिक लाभ बढ़ता जाता है किन्तु एक बिन्दु के बाद ढाल कम लगता है। इसके विपरीत TSS वक्र कर से उत्पन्न कुल सामाजिक व्यय को प्रदर्शित करता है जो <sup>सामाजिक</sup> व्यय के साथ कुल व्यय बढ़ता जाता है किन्तु एक बिन्दु के बाद कुल व्यय बहुत तीव्र गति से बढ़ने लग जाता है।  
 यहाँ TSB तथा TSS वक्र का अंतर शुरु सामाजिक लाभ को दर्शाता है जो MN रेखा से दर्शाया गया है।

अतः सरकार को 0Q मात्रा में व्यय करना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए व्यय करते समय निम्न बातों का ध्यान में रखना पड़ता है -

- ① प्रत्येक व्यय से सीमित उपभोगिता समान रहनी चाहिए। अर्थात् किसी मद पर आवश्यकता से अधिक व्यय करना और दूसरी मद की ~~उपेक्षा~~ उपेक्षा कर देने से सामाजिक लाभ में ह्रास नहीं हो सकती।
- ② व्यय ऐसा हो कि उत्पादन बढ़े। इस चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं -

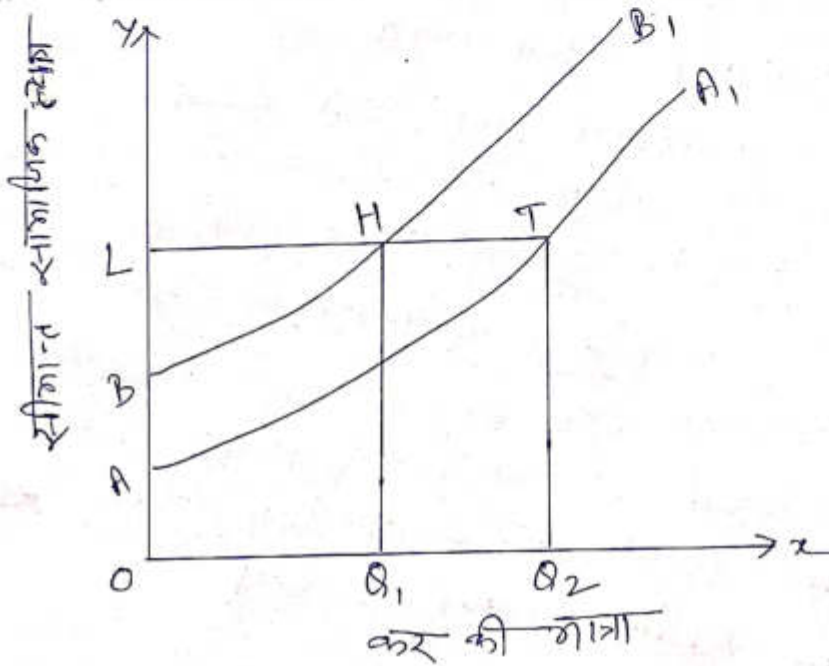


उपर्युक्त चित्र में AA वक्र कृषि पर किया गया सामाजिक व्यय तथा DD वक्र सुरक्षा पर किया गए सामाजिक व्यय को दर्शाता है। दोनों से प्राप्त सीमित सामाजिक लाभ की स्थिति  $HA = TQ_2$  होगा। अतः कृषि पर  $0Q_1$  तथा सुरक्षा पर  $0Q_2$  मात्रा में व्यय किए जाए तो दोनों से सीमित सामाजिक लाभ समान मात्रा में प्राप्त होगा और यही अधिकतम सामाजिक लाभ होगा।

अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए कर लगाते समय भी निम्न बातों का ध्यान में रखना

पड़ता है -

- Ⓐ करारोपण कर देना की शक्ति में आधार पर किया जाना चाहिए। ताकि सभी व्यक्तियों पर समान रूप से कर का भार पड़े।
- Ⓑ करारोपण के समग्र काम करने एवं व्यक्तियों की इच्छा से योजना पर बुरा प्रभाव न पड़े। इसे रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है -



उपरोक्त चित्र में  $AA_1$  तथा  $BB_1$  वक्र A तथा B व्यक्तियों द्वारा कर आना करने से सीमांत सामाजिक हानि को प्रदर्शित करता है। कुल हानि उसी अवस्था में न्यूनतम होगी यदि A तथा B का सीमांत सामाजिक हानि बराबर होगा। अतः सरकार A व्यक्ति पर  $OQ_2$  तथा B व्यक्ति पर  $OQ_1$  के बराबर कर लगाएगी क्योंकि यहाँ  $TQ_2 = HQ_1$ ।

अर्थात् इस सिद्धान्त का बहुत अधिक महत्व है किन्तु व्यवहार में आनेको कठिनाईओं उत्पन्न होती है जो कि ध्यानलिखित हैं -

सर्वप्रथम करो से प्राप्त सीमांत अनुपयोगिता तथा राजकीय व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का पता लगाना तथा इसके सांख्यिक स्थापित करना बहुत ही कठिन कार्य है।

सरकारी व्यय का उद्देश्य सामान्यतया

भविष्य में आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ बनाना होता है।  
परन्तु लाभ कर्त के लिए जो राशि संग्रह की जाती  
है, उसे वर्तमान में ही वसूल किया जाता है।  
इस प्रकार करा का प्रभाव तत्काल फ़ैला जा सकता है।  
जबकि लाभ का प्रभाव भविष्य में पड़ता है। इसी  
स्थिति में जी करा की वर्तमान अनुपयोगिता तथा  
लाभ से भविष्य में मिलने वाली उपयोगिता का  
अनुमान लगाना कठिन कार्य है।

करारोपण द्वारा प्राप्त रकम के लाभ से  
समाज के कुछ वर्गों को लाभ होता है। इस लाभ  
को जी जीक बीक अपना कठिन कार्य है।

उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद  
बहुत दूर तक इस सिद्धान्त को व्यवहारिक रूप  
दिया जा सकता है। सरकार अपनी आर्थिक नीतियों  
पर विचार करते हुए समस्त आवश्यकता सामाजिक  
लाभ का विशेष ख्याल रखे।

—X—

Dr Sandhya Rani  
Dept of Economics  
Maharaja college